

मध्य प्रदेश शास

स्कूल शिक्षा विभ

मंत्रालय

क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006

भोपाल, दिनांक 25/08/2006

प्रति

आयुक्त

लोक शिक्षण

मोप्रो भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है ।

संलग्न- परिशिष्ट एक एवं दो

हस्ताक्षर :-

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्र. क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006

प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25.08.2006

1- सचिव, मोप्रो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

2- सचिव, मोप्रो शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।

3- सचिव, मोप्रो शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल ।

4- सहायक संभागीय आयुक्त, मोप्रो

5- सहायक कलेक्टर, मोप्रो ।

6- सहायक सचिव संचालक, लोक शिक्षण, मोप्रो ।

7- सहायक जिला शिक्षा अधिकारी, मोप्रो ।

हस्ताक्षर :-

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
- 2- रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

Y

राही/-
अवर सचिव,
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शालाएँ खोलने हेतु वर्तमान तथा नये मापदण्ड

क्र.	मंद	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				हाई स्कूल	
		वर्तमान मापदण्ड		नये मापदण्ड		वर्तमान मापदण्ड	हाई स्कूल
		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा / कन्या शाला		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला
1	जनसंख्या	3000	6000	3000	1500	3000	3000
2	इसी प्रकार की विद्यमान शाला से निकटतम दूरी	5 कि.मी.	5 कि.मी.	8 कि.मी.	3 कि.मी.	3 कि.मी.	3 कि.मी.
3	पोषक शालाओं में फोडर कक्षाओं को कुल दर्ज संख्या	100	100	100	80	80	80
4	कालांतर में भवन निर्माण हेतु शासकीय / निजी (दान की) उपलब्ध भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय
5	जन सहयोग	अन्य बातें समान होने पर जनसहयोग उपलब्ध होने पर किसी स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।					
6	टीप	1. यदि क्षेत्र की शालाओं में कुल दर्ज छात्रा संख्या इतनी हो कि शिक्षक - छात्रा अनुपात 1:45 से अधिक हो गया हो तो दूरी की शर्त लागू नहीं होगी। 2. किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। 3. शाला की स्थापना करने वाली जनपद पंचायत को यह संकल्प पारित करना होगा कि वह शीघ्र ही विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करेगा। हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु विभाग से तथा प्राथमिक / कनिष्ठ विद्यालय हेतु जनसहयोग रा.यो. आदि के वजह से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।					